दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

Social Justice Union, Govt. Registered

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 09 अगस्त 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 312

वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य

रायपुर। छत्तीसगढ प्राकृतिक वन संपदा से सम्पन्न है और यहां सदियों से निवासरत आदिवासी समुदाय के लोगों को राज्य में एक अलग पहचान हैं। यहां की पहचान लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज, नृत्य महोत्सव अपनी गौरवशाली संस्कृति को बनाकर रखी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों को सभी अधिकार देने की पहल शुरू की । वनांचल क्षेत्र में बरसों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को 59 हजार 791 वन अधिकार पत्र दिया गया है। ताकि अपनी काबिज भूमि में खेती-बाड़ी कर आर्थिक तरक्की कर सकें। मुख्यमंत्री ने किसानों की जमीन वापसी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 2500 रूपए प्रति मानकर बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा करके किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। वेल्यू एडीशन करके न सिर्फ़ वनवासियों की आय में बढ़ोतरी की है, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदाय के जुड़े हर मसले को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से निराकरण करने के साथ उनकी बेहतरी के लिए कदम उठा रही है।

राज्य में लगभग पौने पांच वर्ष में 59 हजार 791 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका कुल रकबा 33,238.504 हेक्टेयर है। इसी प्रकार 25 हजार 109 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए है, जिसका कुल रकबा 11,81,587.935 हेक्टेयर है। देश में सर्वप्रथम नगरीय क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय करने की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य में की गई। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में अब तक 3,964 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किए गए हैं, इनका कुल रकबा 17,292,37.103 हेक्टेयर है। राज्य में अब तक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को 23 हजार 571 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, जिनका 19,124.408 हेक्टेयर वन भूमि, इसी प्रकार 2360 सामुदायिक वन अधिकार पत्र पर कुल रकबा 1,22,679.174 हेक्टेयर और 184 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया है जिसका कुल रकबा 1,44,525.947 हेक्टेयर प्रदान किया गया।

वन अधिकार पट्टाधारी वनवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनके पट्टे की भूमि का समतलीकरण, मेड़बधान, सिंचाई की सुविधा के साथ साथ,खाद बीज एवं कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। वन भूमि पर खेती करने वाले वनवासियों को आम किसानों की तरह शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। वनांचल में कोदों, कुटकी, रागी की बहुलता से खेती करने वाले आदिवासियों को उत्पादन के लिए प्रति एकड़ 9 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान है, इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ इन्हें दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा जिले को देंगे 1000 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बस्तर और सरगुजा जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर इन दोनों आदिवासी बहुल जिलों को 1007 करोड़ 55 लाख रूपए की लागत के 2848 कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 8 अगस्त को बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेंगें तथा 9 अगस्त को जगदलपुर के पीजी कॉलेज ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम में 674 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत के 2580 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री जगदलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सरगुजा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर जिले को 333 करोड़ 35 लाख रूपए की लागत के 268 कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बघेल जगदलपुर में 523 करोड़ 87 लाख रूपए की लागत के 2118 कार्यों का भूमिपूजन तथा 150.32 करोड़ रूपए की लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह सरगुजा जिले के सीतापुर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 142 करोड़ 48 लाख रूपए की लागत के 135 कार्यों का लोकार्पण तथा 190 करोड़ 87 लाख रूपए की लागत के 133 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इन दोनों ही कार्यक्रमों में राज्य शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि और सामग्री का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री 8 अगस्त को जगदलपुर पहुंचने के बाद वहां महारानी अस्पताल में निर्मित अंबक नेत्र चिकित्सालय और दलपत सागर के समीप सेहत बाजार (मिलेट्स कैफे) का लोकार्पण करेंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

मुंबई में आतंकी हमले की धमकी देने वाला गिरफ्तार, मंत्रालय कंट्रोल रूम में आया था कॉल

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को धमकी भरा कॉल करने के लिए गिरफ्तार किया है। उसने मंत्रालय के लैंड लाइन पर फोन किया और कहा कि एक-दो दिन में मुंबई में आतंकी हमला होगा। कॉलर को कुछ ही घंटे में ट्रेस कर लिया गया। कॉलर कांदीवली इलाके का है और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी का नाम प्रकाश खिमानी है। पुलिस की मानें तो फिलहाल, कॉल करने की वजहों का पता लगाने के लिए मुम्बई पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। हालांकि, पुलिस को शक है कि शराब के नशे में कॉलर ने फोन किया था। बता दें, मुंबई पुलिस ने कहा कि सोमवार देर रात को आरोपी ने महाराष्ट्र मंत्रालय में फोन कर मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी थी। फोन पर उनसे कहा था कि मुंबई में एक-दो दिन में आतंकी हमला होगा। आरोपी की उम्र 61 साल है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जालंधर में लुटेरों के हौसले बुलंद, गन प्वाइंट पर मॉडल टाउन से कार लूटकर फरार

जालंधर (आरएनएस)। जालंधर में दिनदहाड़े मॉडल टाउन में कार लूट का मामला सामने आया है। गन प्वाइंट पर स्विफ्ट कार लूटे जाने की खबर है। इस संबंध में पीड़ित लक्ष्य निवासी गुरू तेग बहादुर नगर ने बताया कि वह किसी काम से माडल टाऊन के निकट श्री गुरूद्वारा साहिब के निकट आया था। इसी दौरान पैदल ही तीन युवक उसके पास आए। उसे गन प्वाईंट पर ले कर मार डालने की धमकी दी और कार लूट ले गए। पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है। थाना नम्बर 6 की पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामला ट्रेस कर लिया जाएगा।

चोरी के आरोप में मुंडन कराकर पिटाई करने के आरोप में 1 गिरफ्तार

गया (आरएनएस)। बिहार के गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने पकडक़र मुंडन करा दिया और फिर उसे बांधकर उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि रविवार की रात इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की जांच में यह मामला सत्य पाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर पीड़ित परिवार की खोज की। इस घटना में चोरी के आरोप में युवक को हैंडपंप में बांधकर लोगों द्वारा पिटाई करने, कपड़े उतारने, उसके सिर का मुंडन, आइब्रो, मूंछे काटे जाने का मामला सामने आया था। पीड़ित की मां के बयान पर सोमवार को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भारती ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने डेल्हा थाना अंतर्गत बैरागी मोहल्ला के रहने वाले अनिल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम विस्फोट, पुलिसकर्मी समेत सात लोगों की मौत

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में एक वाहन के पास एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक स्थानीय राजनेता, सरकारी अधिकारी और पुलिस सहित कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। पंजगुर के उपायुक्त अमजद सोमरो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि यह घटना बीती देर रात हुई जब प्रांत के पंजगुर जिले में एक शादी समारोह से लौट रहे एक यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य लोगों के वाहन सडक़ किनारे रखे बम की चपेट में आ गए। पुलिस ने कहा कि बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोट किया गया और विस्फोट में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और अपराधियों को पकडऩे के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

आईआईटी हैदराबाद की छात्रा ने मानसिक तनाव के कारण की आत्महत्या

हैदराबाद (आरएनएस)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद की एक छात्रा ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। ममिता नायक (21) सोमवार रात अपने छात्रावास के कमरे में लटकी हुई पाई गई। ओडिशा की रहने वाली छात्रा पिछले महीने एम.टेक प्रथम वर्ष में शामिल हुई थी। उसके सहपाठियों ने उसे पंखे से लटका हुआ पाया। उन्होंने छात्रावास अधिकारियों को जानकारी दी और संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस को सूचित किया। उसके शरीर को शव परीक्षण के लिए ले जाया गया। पुलिस को कथित तौर पर उसके कमरे से एक सुसाइड लेटर मिला है, इसमें उसने लिखा है कि उसकी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वह मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठा रही है। आईआईटी हैदराबाद, हैदराबाद के पास संगारेड्डी जिले के कांडी में स्थित है। एक महीने से भी कम समय में आईआईटी हैदराबाद के छात्र द्वारा की गई यह दूसरी आत्महत्या है। इसके पहले डी. कार्तिक (21) ने विशाखापत्तनम में समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। वह बी.टेक (मैकेनिकल) द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसने 17 जुलाई को परिसर छोड़ दिया था। उसका शव 25 जुलाई को विशाखापत्तनम समुद्र तट पर बरामद किया गया था। एक साल में आईआईटी हैदराबाद के चार छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल सितंबर में, राजस्थान की मूल निवासी मेघा कपूर (22) ने आईआईटी हैदराबाद परिसर के पास, संगारेड्डी शहर में एक लॉज से कूदकर जान दे दी थी। उसने तीन महीने पहले आईआईटी-एच से बी.टेक पूरा किया था और एक लॉज में रह रही थी।

अगस्त में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नंद्याल के मूल निवासी और एम.टेक द्वितीय वर्ष के छात्र जी. राहुल ने अपने छात्रावास के कमरे में फांसी लगा ली थी।

मणिपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 जिलों से लूटे गए 9 हथियार बरामद किए

इंफाल (आरएनएस)। मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों से लूटे गए नौ हथियार बरामद किए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों और सशस्त्र हमलावरों के बीच बिष्णुपुर जिले के क्वाक्टा और तेराखोंगसांगबी इलाकों और चुराचांदपुर जिले के मुआलनगाट, गोथोल, फोलजांग इलाकों में भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को खदेड़ दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो जिलों के इन इलाकों से लूटे गए नौ हथियार बरामद किए, दोनों जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है. इस बीच, मणिपुर सरकार ने एक आदेश के तहत बिष्णुपुर जिले के मोइरंद लमखाई में चेक गेट पर असम राइफल्स को राज्य पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा तैनात कर दिया है।

झटका : ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की याचिका खारिज

प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया।

वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति के लिए मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बिसेन व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। अदालत का कहना था कि याची ने वाराणसी कोर्ट में सिविल वाद दायर कर रखी है। वह जो कुछ आदेश उच्च न्यायालय से लेना चाह रही है वह सब कुछ वाराणसी की निचली अदालत में भी अर्जी दाखिल कर मांग कर सकती हैं। याची के इस कथन पर कि वह अपनी बात लोवर कोर्ट वाराणसी में रखेगी इस आधार पर उसके द्वारा याचिका वापस लेने पर खारिज कर दिया।

पांटून पुल घोटाले पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, जांच के दिए आदेश

प्रयागराज (आरएनएस)। महाकुम्भ में लोक निर्माण विभाग की तरफ से पांटूनों के निर्माण और ढुलाई में की गई गड़बड़ी की लीपापोती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। जांच में विलंब होने के बाद शासन की ओर से लोक निर्माण विभाग विकास के प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर तत्काल आख्या मांगी है।मामले विद्युत यांत्रिक खंड के अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

बता दें कि महाकुम्भ 2025 के लिए पांटूनों का निर्माण लंबे समय से शुरू हुआ है। इस क्रम में आरोप लगाया गया कि अफसरों ने लापरवाही से दूसरे ठेकेदारों को काम दिया। आरोप है कि जिन्हें काम दिया गया न तो लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत हैं और न ही उन्होंने निविदा के साथ विभाग की शर्तों को लगाया था। अफसरों ने नियम की अनदेखी कर ऐसी एजेंसी को काम दिया, जिसने बढ़े हुए टेंडर पर बोली लगाई थी। मामले की कई चरणों में शिकायत हुई। 22 अगस्त 2022 को पहली और 29 मार्च 2023, 25 मई 2023, 20 जून 2023 को दूसरी, तीसरी और चौथी बार शिकायत की गई। इस शिकायत में अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

लंबे समय से अफसर इस जांच को पूरा नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों शासन के विशेष सचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी ने प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग विकास को पत्र लिखकर जांच आख्या मांगी है। पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रकरण मुख्यमंत्री के आदेश से आच्छादित है। ऐसे में जांच में शीघ्रता करें।

मिली जानकारी के अनुसार विद्युत यांत्रिक खंड में वित्तीय अनियमितता की यह शिकायत भाजपा कानूनी और विधि विभाग के जिला संयोजक भोलानाथ पांडेय ने मुख्य अभियंता से की थी। इसमें उन्होंने एक्सईएन दिनेश कुमार पर चहेती फर्मों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी तरह इंजीनियर इन चीफ को दिए पत्र में कहा गया था कि विद्युत यांत्रिक खंड में मनमाफिक फर्मों से स्वीकृत बजट के विपरीत न्यूनतम दर पर निविदा डलवाकर शेष धनराशि डकार ली गयी है।

बताते है कि उच्च न्यायालय के कोर्ट नं. आठ, 10 और 18 में कराए गए विद्युतीय कार्यों में आगणित धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत न्यूनतम रेट पर निविदा डालकर शेष धनराशि का सप्लाई आर्डर के माध्यम से फर्जी भुगतान कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कोरोना काल में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निलंबित एक्सईएन दिनेश यादव के कार्यकाल का वैरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ), वैरिएबल रेफ्रिजरेंट वाल्यूम (वीआरवी) एसी का अनुबंध गठित कर चहेती फर्म को फर्जी भुगतान किया गया था।

इसी तरह उच्च न्यायालय में नेटवर्किंग के कार्य में भी मानक को ताक पर रखकर लाखों रुपये का गोलमाल किया गया और एग्रीमेंट के तहत गारंटी वारंटी के दस्तावेज नहीं सौंपे गए थे। ऐसे में इन कार्यों से जुड़ी निविदा के अनुबंधों के अलावा कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की थी। जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके।

राहुल गांधी को मिला सरकारी बंगला, बोले-पूरा हिंदुस्तान मेरा घर

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूरा भारत उनका घर है। सूत्रों से खबर आई कि लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता बहाल करने के एक दिन बाद उन्हें अपना आधिकारिक बंगला फिर से आवंटित कर रहा है। दरअसल, पत्रकारों ने राहुल गांधी से 12 तुगलक लेन स्थित उनके बंगले के फिर से आवंटन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। हालांकि, बंगले के दोबारा आवंटन की आधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि 12 तुगलक लेन वाला मकान उन्हें आवंटित कर दिया गया है। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था और उन्हें आधिकारिक आवास खाली करना पड़ा था। 24 मार्च को अयोग्य ठहराए जाने के एक महीने बाद राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आवास खाली कर दिया था।

भीषण गर्मी से अमेरिका में 147 लोगों की मौत

वाशिंगटन । देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी के कारण इस महीने अमेरिका के एरिजोना, नेवादा और टेक्सास राज्यों में 147 लोगों की मौत हो गई। भीषण गर्मी से ये तीन राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

एरिज़ोना के पिमा और मैरिकोपा काउंटियों में क्रमश: 64 और 39 मौतें हुईं; जबकि 26 मौतें क्लार्क काउंटी, नेवादा में हुईं; और टेक्सास के वेब व हैरिस काउंटी में क्रमश: 11 और सात लोगों की मौत हुई। कैलिफ़ोर्निया, दक्षिण के कुछ हिस्सों और मध्यपश्चिम में भी गर्मी से संबंधित कई मौतें दर्ज की गईं।

मैरिकोपा काउंटी में आधिकारिक तौर पर गर्मी से संबंधित कम से कम 39 मौतें दर्ज की गईं और 312 और मौतों की जांच चल रही है।

जून के अंत में तापमान रिकॉर्ड-तोड़ स्तर तक बढ़ गया और जुलाई के दौरान दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम के अधिकांश हिस्सों में तापमान बढ़ता रहा। जून से जुलाई तक लगातार 31 दिन 43 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान के साथ फीनिक्स किसी भी अमेरिकी शहर का सबसे गर्म महीना रहा।

अब जमीन घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन, 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया

रांची (आरएनएस)। ईडी ने रांची के जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। उन्हें 14 अगस्त को ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके पहले ईडी ने माइनिंग घोटाले में भी हेमंत सोरेन से पिछले साल 22 नवंबर को लगभग दस घंटे तक पूछताछ की थी। माइनिंग घोटाले के बाद अब जमीन घोटाले में पूछचाछ से सीएम की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

ईडी रांची के जमीन घोटाले में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, रांची के न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, कोलकाता के कारोबारी दिलीप कुमार घोष और अमित कुमार अग्रवाल सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस घोटाले में ईडी इन दिनों रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जेल में बंद झारखंड के चर्चित पावर लायजनर प्रेम प्रकाश से भी बीते हफ्ते ईडी ने दो दिनों तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में ईडी को कुछ ऐसे साक्ष्य हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर वह सीएम से पूछताछ करना चाहती है।

बता दें कि जमीन घोटाले का पहला जो मामला सामने आया था, उसमें रांची में सेना की कब्जे वाली तकरीबन 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री गलत तरीके से तैयार किए गए कागजात के आधार पर की गई थी। इस मामले का खुलासा रांची के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रांची नगर निगम ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद ईडी ने इसी प्राथमिकी को इसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की। नवंबर 2022 में व्यापारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापा पड़ा था। इस छापे में कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। ईडी ने दूसरी बार 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बडग़ाईं अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप समेत जमीन के कारोबार से जुड़े 21 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने सेना के कब्जे वाली जमीन के घोटाले की जांच शुरू की तो जानकारी मिली कि कई और भू-खंडों की खरीद बिक्री फर्जी कागजात के आधार पर की गई है। एजेंसी अब तक सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर चुकी है।